

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 93/2024

GCMS NO 2024/153

1. रामकरण पुत्र कन्हैया
2. मलखान पुत्र कन्हैया
3. श्रीमती भुरवाई पत्नि रामकरण
4. कमल बाई पत्नि मलखान समस्त जातियान मीना निवासीयान लीलोटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला



अपीलांत

बनाम

1. राजूलाल पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी कारवाड मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो

(अपील विरुद्ध मुं० नं० 171/09 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.8.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी)
अभिभाषक अपीला० श्री राधेश्याम शर्मा
अभिभाषक रेस्पो० श्री संजय शर्मा

दिनांक 28.11.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.8.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो० द्वारा वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख० न० 850 रकबा 2 ऐयर, 851 रकबा 1 ऐयर बारानी तीन वाके ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन सिटी मे फौलीपुरा से कोटरी सडक के सहारे स्थित है। उक्त दोनो नम्बर का वशमूल ख० न० 853 का वादी ने एक ही चक बना रखा है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के लठैत व्यक्ति है। उक्त भूमि सडक किनारे स्थित होने के कारण बाजारू कीमत बढ गई है इसलिए प्रतिवादीगण विवादित भूमि मुतजिका मद न० 1 वाद पत्र पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है तथा वादीगण को वेदखल करना चाहते है। उक्त भूमि मे वादी द्वारा लगाये गये दो तीन हरे वक्षो बबूलो को प्रतिवादीगण दिनांक 10.8.09 को चोरी की नियत से काट कर ले गये जिसकी प्राथमिकी वादी द्वारा दर्ज कराने की कहने पर प्रतिवादीगण नाराज हो गये और वादी को भूमि से वेदखल करने की ऐलानिया धमकी दो गइ। तथा काश्त नही करने की धमकी भी दी गई। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना लाजमी हुआ। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त तथा खातेदारी की भूमि ख० न० 850 व 851 वाके ग्राम कारवाडी मीना तहसील हिण्डौन मे किसी भी भाग पर कब्जा ना करे वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा भूमि को वेस्ट डेमेज एलीनेट तथा ट्रासफर नही करे। रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो० द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांतगण/प्रतिवादीगण की ओर से यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्र की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिवाज तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिकी पारित करने से पूर्व तीन तनकीयात कायम की गई जिस पर तनकी बार निर्णित नहीं कर अपने निर्णय में यह कही भी अंकित नहीं किया कि जो तनकी वादी को साबित करनी थी वो वादी द्वारा साबित की गई व जो तनकी प्रतिवादी को साबित करनी थी वो प्रतिवादी द्वारा साबित नहीं की गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी कानून की मंशा के खिलाफ पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। रेस्पो/वादी ने अपना जिरह के बयानों में यह अंकित किया था कि दिनांक 13.8.09 को अंतिम बार अपीलांट/प्रतिवादीगण ने धमकी दी थी उसके पश्चात कोई धमकी नहीं दी तथा बिना कोई वाद कारण अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का उक्त दावा डिकी करने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है। खसरा न० 850 व 851 पर वादी/रेस्पो० का आज तक न तो कोई कब्जा रहा और ना ही कभी उपयोग उपभोग रहा तथा बिना कब्जा व उपभोग उपयोग के बिना बेदखली रिलीफ वादी का उक्त दावा डिकी करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादीगण की भूमि खसरा न० 1013 वाके ग्राम कारवाड मीना में स्थित है तथा उक्त भूमि में होकर सडक निकल जाने के पश्चात अपीलांट/प्रतिवादीगण की भूमि का ही 2-3 ऐयर रकबा सडक के दूसरी तरफ रह गया है जिसके मू प्रबंध विभाग ने ख० न० 850 व 851 कायम किये हैं तथा उक्त भूमि सडक के सहारे वेशकीमती होने के कारण अपीलांट/प्रतिवादीगण से जबरन छीनना चाहता है जबकि रेस्पो/वादी का उक्त भूमि से कोई संबंध वास्ता नहीं रहा इस बिन्दु पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर भारी कानूनी भूल की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर तीन गह पाटोर पोशे हुए हैं तथा अपीलांट का ही उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है तथा कब्जे के अभाव में वादी/रेस्पो० का उक्त वाद स्थाई निषेधाज्ञा मेंटेवल नहीं होने के कारण भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिकी पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण/अपीलांटगण के बयानों पर गौर नहीं कर भारी कानूनी भूल की है। तथा अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में कही भी प्रतिवादीगण के बयानों का डिस्कस नहीं किया है इससे स्पष्ट साबित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिकी बिना माईण्ड एप्लाइ किये ही पारित किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का न तो अपने निर्णय में हवाला दिया और ना ही चस्पा किया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी मनमानी होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2.8.24 को बहस सुनी गई तथा दिनांक 16.8.24 वास्ते आदेश नियत की गई। दिनांक 16.8.24 के पश्चात अपीलांट/प्रतिवादीगण उक्त निर्णय व डिकी के बारे में पूछते रहे तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटगण ने दिनांक 12.9.24 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 21.10.24 को पारित की जबकि अपने निर्णय में दिनांक 30.8.24 को ही निर्णय व डिकी पारित करना बताया है। अगर दिनांक 30.8.24 को ही निर्णय व डिकी पारित हो जाती तो अपीलांट/प्रतिवादीगण को दिनांक 12.9.24 को ही निर्णय व डिकी की नकल प्राप्त हो जाती लेकिन अपीलांट/प्रतिवादीगण को उक्त निर्णय व डिकी की नकल दिनांक 22.10.24 को प्राप्त हुई जो करीबन डेढ माह के पश्चात नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार नकल मिलने से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः

राजेश्वर अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 30.8.24 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा है जबकि सत्यता यह है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी/रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काशतकार है। जिस पर वादी काशत कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन भी मिथ्या है कि बिना वाद कारण के दावा चलने योग्य नहीं था, जबकि वादी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में वाद कारण का स्पष्ट उल्लेख मय दिनांक तक का उल्लेख किया गया है। वादी/रेस्पो0 द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 व 2 पेश की गई है जिससे वादी का वाद पत्र सिद्ध होता है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2.8.24 को बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश दिनांक 16.8.24 नियत की गई थी, परन्तु दिनांक 16.8.24 को पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 16.8.24 से दिनांक 30.8.24 वास्ते आदेश नियत की गई है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.8.24 को विधिवत रूप से आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज होने से खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पो0 का कब्जा नहीं होकर अपीलांट का कब्जा काशत है तथा उस पर अपीलांट द्वारा दो गह पाटोर पोश बना रखी है। इस संबंध में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा सिद्ध हो सके जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध छाया प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत 2080 में खसरा नं०-850 व 851 में वादी/रेस्पो0 राजू पुत्र रामफूल की काशत दर्ज है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि बिना वाद कारण दावा चलने योग्य नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दावे के अवलोकन से जाहिर है कि वाद कारण दिनांक 13.8.09 को प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा वादी/रेस्पो0 को उक्त भूमि से जबरदस्ती कब्जा करने तथा बेदखल करने की धमकी देने का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन भी साबित नहीं होता है। वादग्रस्त आराजीयात का रेस्पो/वादी रिकार्डेड खातेदार है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 प्रदर्श 1 से होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 171/09 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.8.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(लक्ष्मी कर्मा) अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी

डिगरी बसीगे अपील
(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीयानी)
(Civil Procedure code, Appendix G)
अज अदालत राजख अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर
बड़जलास श्री लक्ष्मीकांत वालोत आर.ए.एस.

1. रामकरण पुत्र कन्हैया
2. मलखान पुत्र कन्हैया
3. श्रीमती भुरबाई पत्नि रामकरण
4. कमल बाई पत्नि मलखान समस्त जातियान मीना निवासीयान लीलोटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांत

बनाम

1. राजूलाल पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी कारवाड मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो०

अपील संख्या 93/2024 निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी दिनांक 30.8.24 दावा स्थाई निषेधाज्ञा । यह अपील संख्या 93/24 व तारीख 28.11.25 रुबरू हमारे व हाजिरी श्री राधेश्याम शर्मा अभिभाषक मिन जाति अपीलांत तथा रेस्पो० श्री संजय शर्मा उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति समाप्त के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी प्रकरण संख्या 171/09 निर्णय व डिकी दिनांक 30.8.24 की पुष्टि की जाती है।



दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 28.11.2025 को जारी किया।

राजख अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपील	रूपये	पैसे	रेस्पो०	रूपये	पैसे
स्टाम्प अपील	---	---	स्टाम्प वकालतनामा	---	---
स्टाम्प वकालतनामा	---	---	स्टाम्प अर्जी	---	---
इजराय हुक्मनामा	---	---	इजराय हुक्मनामा	---	---
वकील फीस बाबत	---	---	महन्ताना वकील	---	---